जनसत्ता

बेहतरी के कदम

आर्थिक मंदी से उबरने के दबाव झेल रही सरकार ने दो बड़े क्षेत्रों में बेहतरी के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। आवास और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से सत्तर हजार करोड़ रुपए से अधिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसमें बीस हजार करोड़ रुपए की मदद अधूरी पड़ी आवासीय योजनाओं के लिए और पचास हजार करोड़ रुपए की राशि निर्यात क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए तय की गई है। आवासीय योजनाओं को पूरा कराने के लिए सरकार दस हजार करोड़ रुपए मुहैया कराएगी और दस हजार करोड़ रुपए अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराने के उपाय किए जाएंगे। इसमें आवास वित्त कंपनियों को विदेशी स्रोतों से धन जुटाने संबंधी नियमों में ढील दी जाएगी। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए कर्ज पर ब्याज दरों में छूट का भी प्रावधान किया गया है। अनुमान है किइससे साढ़े तीन लाख आवास खरीदारों को लाभ मिलेगा। इसी तरह सरकार का दावा है कि निर्यातकों को इतना लाभ दिया जाएगा, जितना अभी सारी योजनाओं को मिला कर नहीं दिया जा रहा है। चालीस से पैंतालीस हजार करोड़ रुपए के करों का रिटर्न अदा किया जाएगा। इससे सरकार पर करीब पचास हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा छोटे और मझोले निर्यातकों के ऋण की ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। स्वाभाविक ही इस कदम से अर्थव्यवस्था में कुछ गति आने की उम्मीद बनी है।

दरअसल, इस वक्त विकास दर पिछले छह सालों के सबसे निचले स्तर पर है। उसमें निर्यात और रियल एस्टेट का योगदान घट कर चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। निर्यात को बढ़ावा देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बाजार न मिल पाने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। इसलिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात संबंधी नियम-कायदों को लचीला बनाने और उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने के उपायों पर विचार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस तरह सरकार के इस कदम से निस्संदेह निर्यातकों में कुछ उत्साह का वातावरण बनेगा। इसी तरह सरकार ने बेनामी संपत्ति जमा करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रियल एस्टेट के क्षेत्र में कुछ नियम-कायदों को कड़ा किया था। फिर भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भी उछाल आया था। इसकी वजह से भी अनेक आवासीय परियोजनाएं सुस्त पड़ गई थीं। अब नए कदम से इस क्षेत्र में कुछ गति आने की उम्मीद जगी है।

मगर फिलहाल बड़ी समस्या यह है कि लोगों की क्रयशक्ति काफी घट गई है। इसलिए लोग बहुत सोच-समझ कर बाजार में निवेश कर रहे हैं। इसी का असर है कि आवासीय योजनाओं में निवेश काफी घट गया है। स्थिति यह है कि देश में तेरह लाख से ऊपर तैयार मकानों के खरीदार नहीं हैं। अब सरकार रुकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराएगी तो मकानों की संख्या और बढ़ जाएगी। इसलिए ब्याज दरों में छूट और आवासीय परियोजनाएं चलाने वाली और आवास वित्त कंपनियों को राहत देने से मकानों की बिक्री में कितनी गति आएगी, यह देखने की बात है। इसके अलावा सबसे महत्त्वपूर्ण बात है निर्यात क्षेत्र को शक्तिशाली बनाना। घरेलू बाजार सिकुड़ चुका है। ऐसे में अपने उत्पाद को बाहरी बाजार में खपाने की जरूरत है। पर दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी की चपेट में हैं। ऐसे में यह कदम भी कितना प्रभावी होगा, समय बताएगा। सरकार को ऐसे छिटपुट उपायों पर ध्यान देने के बजाय समग्र आर्थिक उपायों पर विचार करना चाहिए।

योजना और सवाल

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सम-विषम योजना शुरू करने की बात कही है। पिछले कई सालों से दिल्ली जिस तरह वायु प्रदूषण की मार झेल रही है, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार की यह कवायद एक अच्छा प्रयास है। सड़क पर अगर वाहन कम चलें तो निश्चित रूप से एक सीमा तक वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली के वायु प्रदूषण में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की भागीदारी चालीस फीसद है। यह कम नहीं है। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार समय रहते एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन योजना की घोषणा के साथ ही इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल सिर्फ योजना पर नहीं, बल्कि इसे लागू करने के पीछे दिल्ली सरकार की गंभीरता को लेकर ज्यादा हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने ही यह कह दिया है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सम-विषम योजना की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल फिर यही खड़ा होता है कि जहरीली हवा में हांफती दिल्ली को आखिर प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का उपाय क्या है।

दिल्ली में हर साल नवंबर-दिसंबर में प्रदूषण की मात्रा बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाती है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक, पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाए जाने से निकलने वाला धुआं दिल्ली की ओर आना और दूसरा कारण दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए सात बिंदुओं के आधार पर कार्ययोजना बनाई है। इसमें दीपावली पर पटाखे न जलाने की अपील, कूड़ा और पेड़ों की पत्तियां जलाने पर रोक, धूल से बचाव, पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने जैसे कदम भी शामिल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से एक भी उपाय अब तक कारगर साबित नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में अब भी लाखों ऐसे वाहन हैं जिनकी पंद्रह साल की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन सड़क पर बेधड़क दौड़ रहे हैं। पिछले चार साल में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई की होगी। जहां तक दीपावली पर पटाखे फोड़ने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही पाबंदी लगा चुका है। लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कूड़ा जलता देखा जा सकता है। राजधानी में कूड़े के जो पहाड़ खड़े हैं, उनको हटवाने के लिए पिछले चार साल में क्या कोई बड़ा फैसला हुआ?

सम-विषम योजना 2016 में दो बार लागू की गई थी। लेकिन इसके नतीजों को लेकर ही परस्पर विरोधी रिपोर्टें और खबरें आती रहीं। दिल्ली सरकार का दावा था कि सम-विषम योजना लागू करने से प्रदूषण में दस से बारह फीसद की कमी आई थी। जबकि कुछ अध्ययनों में यह सामने आया कि इससे हवा में मौजूद घातक कण पीएम 2.5 और कार्बन की मात्रा बढ़ गई थी। सरकार को प्रदूषण से मुक्ति के लिए दीर्घकालिक नीति और उपायों पर काम करने चाहिए थे, जो नहीं हुए। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इतना दुरुस्त बनाया जाए कि लोगों को अपना वाहन निकालने की कम से कम जरूरत पड़े। सम-विषम योजना में जिस तरह छूट की लंबी सूची है उससे इस योजना पर अमल की गंभीरता कम होती है। योजना लागू करनी है तो सख्ती से की जानी चाहिए, सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए नहीं।

कल्पमेधा

समाज की खुशहाली सुरक्षित रखने का एक ही उपाय है, वह यह कि लोगों को अपने मन-मस्तिष्क का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने दिया जाए।
-हेराल्ड लास्की

आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान

जयंतीलाल भंडारी

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया जैसी हालत में है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनके देश के पास कर्ज की किस्तें चुकाने तक के लिए डॉलर नहीं बचे हैं। विकास दर चार फीसद पर आ गई है, जो नौ साल के निचले स्तर पर है। इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार तेरह अरब डॉलर से भी कम रह गया है। पाकिस्तान एक बार फिर आर्थिक मदद के लिए आइएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती और बढ़ा दी है। ऐसे में दुनिया के अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि यदि पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपने का दुस्साहस करता है तो पहले से ही कमजोर पड़ी उसकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती का दौर है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो एकदम खस्ताहाल है और भारी मंदी की चपेट में है। ऐसे में भारत के साथ युद्ध की कल्पना भी उसे नहीं करनी चाहिए। युद्ध से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई वह दशकों तक नहीं कर पाएगा।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट एक नहीं, कई हैं। जहां उसके आंतरिक वित्तीय राजस्व में कमी आ रही है, वहीं बाहरी वित्तीय मदद का संकट भी गहराता जा रहा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और धन शोधन करने वाले देशों पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की एशिया-प्रशांत इकाई की हुई बैठक में पाकिस्तान को काली सूची में डालने का फैसला किया गया था। अब इस पर अंतिम फैसले के लिए अगले महीने एफएटीएफ की बैठक होगी। पाकिस्तान के लिए गंभीर संकट की आहट है। यदि पाकिस्तान को काली सूची में डालने के फैसले पर मुहर लग जाती है तो उसकी आर्थिक स्थिति और गंभीर हो जाएगी।

एफएटीएफ के एशिया प्रशांत समूह ने अपनी जांच में पाया था कि पाकिस्तान ने धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी कुल चालीस मानकों में से बत्तीस का अनुपालन नहीं किया। ऐसे में अब खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आएएमएफ), विश्व बैंक और यूरोपीय संघ आदि से मदद मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर यह होगा कि मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भी पाकिस्तान की रेटिंग गिराने को मजबूर होंगी। रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग से ही देश यह तय करते हैं कि किस देश में निवेश किया जा सकता है। इससे पाकिस्तान में होने वाले निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, निवेशक बिदकेंगे और इससे उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है।

अमेरिका ने भी पाकिस्तान को एक बड़ा आर्थिक झटका दिया है। अमेरिका ने केरी लूगर बर्मन एक्ट के तहत पाकिस्तान को ऊर्जा एवं जल संकट से निपटने के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित मदद में चवालीस करोड़ डॉलर की कमी कर दी है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मुकाबले तो काफी मजबूत है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से नौ गुना बड़ी है। विकास दर, विदेशी मुद्रा भंडार और महंगाई नियंत्रण के मामले में भी भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन पाकिस्तान में हालात इसके उलट हैं। पिछले महीने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (पीबीएस) ने महंगाई के जो आंकड़े जारी किए थे, वे चौंकाने वाले थे। इन आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जुलाई 2019 में पाकिस्तान में महंगाई दर 10.34 फीसद रही, जो पिछले साल जुलाई 2018 में 5.86 फीसद थी। जबकि भारत में महंगाई कम बढ़ी है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया जैसी हालत में है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनके देश के पास कर्ज की किस्तें चुकाने तक के लिए डॉलर नहीं बचे हैं। विकास दर गिरती हुई चार फीसद पर आ गई है जो नौ साल के निचले स्तर पर है। इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार तेरह अरब डॉलर से भी कम रह गया है। पाकिस्तान एक बार फिर आर्थिक मदद के लिए आइएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी मुद्रा एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा हो गई है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया डेढ़ सौ के पार चला गया है। यदि पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपता है तो यह उसका आत्माघाती कदम होगा। बीस साल पहले भी करगिल की लड़ाई में दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब बीस साल बाद भारत पाकिस्तान से किसी भी युद्ध की स्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत स्थिति में है। इस समय भारत का वार्षिक रक्षा बजट पाकिस्तान से पांच गुना ज्यादा है। करगिल युद्ध में दोनों देशों को रोजाना करीब पंद्रह करोड़ रुपए का खर्च आया था। चूंकि करगिल युद्ध कश्मीर के एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित था, इसलिए यह पंद्रह करोड़ रुपए तक ही सीमित रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है की जिस तरह बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत पैमाने पर भारत-पाक युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ रही है, उसमें यह खर्च पांच से दस हजार करोड़ रुपए प्रति सप्ताह से भी अधिक बढ़ सकता है। इतना भारी-भरकम खर्च पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था की मुश्किलें और बढ़ा देगा।

युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ाने के लिए भारत नदियों को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए दुश्मन देश को सबक सिखा सकता है। भारत ने इस साल 21 फरवरी को फैसला किया था कि वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के कारण पाकिस्तान को जो लाभ हो रहे हैं, उन्हें भी रोका जाएगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान चिंतित हो गया है। एक मार्च को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख कर कहा था कि अगर भारत नदियों से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोकता है तो इससे पाकिस्तान के सामने पीने के पानी और कृषि तथा उद्योगों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि भारत अब आतंकी हमले और शत्रुता के मद्देनजर सिंधु जल समझौते को तोड़ दे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी।

इन सबके अलावा पाकिस्तान से युद्ध की चुनौती के बीच भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के साथ-साथ पाकिस्तान रहित दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लिए म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान को मिला कर बनाए गए समूह बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) की संभावना को आगे बढ़ा रहा है। इससे पाकिस्तान का पड़ोसी देशों के साथ कारोबार घटेगा। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होगी।

स्पष्ट है कि पाकिस्तान को भारत के साथ उद्योग-कारोबार की जरूरत बनी हुई है। दुनिया के अर्थविशेषज्ञों का कहा है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी है कि वह पाकिस्तान में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण और विद्वेष का माहौल बंद करे और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ कारोबार संबंध फिर से बहाल करे। यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पस्त होती अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी।

पानी पर लिखी कहानी

रजनीश जैन

दुनिया मेरे आगे

'पानी का न रंग है, न स्वाद, न सुगंध और न इसे परिभाषित किया जा सकता है। यह जीवन के लिए केवल जरूरी नहीं, खुद जीवन है। यह हमें उन तृप्तियों से भर देता है जो इंद्रियों के आनंद से अधिक है।' फ्रेंच लेखक अंटोनिओ डे सेंट की पंक्तियां पानी के रहस्य से हमारा परिचय करा देती है। कहना न होगा कि यह रहस्यमय जल हमें इतनी प्रचुरता में मिला था कि हम इसकी कद्र करना भूल गए। जो भी चीज मनुष्य को इफरात में मिलती है, उसके प्रति वह उदासीन हो जाता है। पिछले तीस-चालीस वर्षों में ही पीने के पानी का संकट विकराल रूप ले चुका है। अखबारों के अंचल के पन्नों और शहरी खबरों में इस भयावह समानता को महसूस किया जा सकता है। इन्हीं समाचारों के बीच कभी-कभी मानसिक दिवालिएपन की झांकी भी नजर आ जाती है, जहां वर्षा के लिए जानवरों के विवाह कराए जाने के हास्यास्पद टोटके आजमाए जाने का जिक्र होता है।

प्रकृति के प्रति उदासीनता के परिणामों का असर नजर आने लगा है। भूजल स्तर हर गुजरते साल के साथ नीचे उतर रहा है। किसी ने कभी कहा होगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। वे पूरी तरह गलत नहीं थे। हमारे ही देश के दो राज्य जिस तरह पानी के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने हुए हैं, उससे डरावने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर उभर आती है। इन दिनों एक तस्वीर लगातार सामने आ रही है। एक नन्हे पौधे के इर्द-गिर्द खड़े करीब पचास लोग वृक्षारोपण की रस्म अदायगी करते कैमरे की तरफ झांकते हैं। इनमे से कितने पर्यावरण को लेकर गंभीर हैं, उस फोटो को देख कर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

आज जरूरत है प्रकृति के प्रति जुनूनी समर्पण की। अच्छी बारिश के बाद तस्वीर में मौजूद अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता कि उस पौधे का क्या हाल है। त्योहार की तरह पेड़ लगाने वालों को समझना होगा कि यह सिर्फ साल में एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमारी जीवन शैली होना चाहिए, तब जाकर हम आगामी पीढ़ी के लिए बेहतर परिस्थितियां निर्मित कर पाएंगे। जल संकट और कुछ नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन शैली और रहन-सहन के बदलते स्वरूप का नतीजा भर है। हमारी पीढ़ी को यह कटु सत्य स्वीकार लेना चाहिए कि उनके समय में पानी एक उत्पाद की तरह बिकना शुरू हो गया है। तरक्की का यह सोपान मानव जाति को किस स्थिति से रूबरू कराएगा, सिर्फ कल्पना की जा सकती है।

पानी की समस्या पर पर्यावरणवादियों और चिंतकों के अलावा फिल्मकारों ने भी अवर्षा को केंद्र में रख कर पानी के महत्त्व को आवाज देने का प्रयास किया है। ख्यात फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने पचास वर्ष पहले महसूस कर लिया था कि पानी का दुरुपयोग और अभाव हमारे जीवन को गहरे तक प्रभावित करने वाला है। इसी संकट को केंद्र में रख कर उन्होंने फिल्म 'दो बूंद पानी' (1971) निर्मित और निर्देशित किया। उसका कथानक और संदेश उस दौर से ज्यादा आज प्रासंगिक है।

आरके नारायण के उपन्यास पर आधारित 'गाइड' (1965) में अवर्षा कथानक के केंद्र में है। एक चोर परिस्थितिवश साधु बन जाता है, लेकिन गांव वालों की अपने प्रति अगाध श्रद्धा के चलते वर्षा के लिए बारह दिन के उपवास की तपस्या कर बैठता है। इधर भूख से उसकी मृत्यु होती है और उधर गांव में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। यह फिल्म देव आनंद को बतौर अभिनेता, विजय आनंद को बतौर निर्देशक और एसडी बर्मन को बतौर संगीतकार तब तक अमर रखेगी, जब तक इस धरा पर सिनेमा मौजूद रहेगा!

अमोल पालेकर निर्देशित अपने आप में अनूठी फिल्म 'थोड़ा-सा रूमानी हो जाए' (1990) पानी को जीवन के कई प्रतीकों में बांधती है। जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास का खत्म हो जाना एक तरह से प्रकृति का पानीविहीन हो जाना है। कविताई शैली में बोले गए संवादों की वजह से नाना पाटेकर और अनिता कंवर की केंद्रीय भूमिका वाली इस फिल्म में भी भारी सूखे के बाद बारिश का आना जीवन में आशा के संचार का प्रतीक बन कर उभरा है।

कल्पना कीजिए कि फिल्म 'लगान' (2001) से भारी सूखा झेल रहे गांव वालों की त्रासदी को निकाल दिया जाए तो फिल्म में क्या बचेगा! 'लगान' अपनी मंजिल से ही भटक जाएगी। फिल्म की शुरुआत में घुमड़ते बादलों का आकाश में जुटना एक उम्मीद जगाता है और गीत खत्म होते-होते उनका गायब हो जाना साफ कर देता है कि इस बार की अवर्षा उनकी जिंदगी के मायने बदल देने वाली है। पानी पर लिखे फिल्मी कथानकों का अंत भले ही सुखांत रहा हो, लेकिन वास्तविक जीवन में परिस्थितियां इस तरह के मौके कम ही देती है। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति नजरअंदाजी की कीमत वर्तमान और आगामी दोनों पीढ़ियों को महंगी पड़ने वाली है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा।

हिंदी और हिंदुस्तान

हर साल 14 सितंबर से शुरू होने वाला हिंदी पखवाड़ा देश की हिंदी संस्कृति और मुख्य रूप से हिंदी भाषा पर नजर डालने के लिए मजबूर करता है। वह भाषा जिसने स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था, आज वह अपना स्थान खोजती नजर आती है। उसने (हिंदी) कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ 'नेकी कर दरिया में डाल' जैसी कहावत चरितार्थ हो जाएगी, जिसने भारतीय धरा को आजादी का तोहफा दिया, वह भारतीय समाज में अंग्रेजी के बाद द्वितीय भाषा बन जाएगी। बेशक गूगल ने हिंदी भाषा को तवज्जो दी हो, दुनिया के छह सौ से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती हो, मगर भारत में आज भी अंग्रेजी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजी को भाषा नहीं, अपितु विद्वता का प्रतीक समझा जाने लगा है और हिंदी जो कभी मां जैसी थी, अपने परिचय को मोहताज नजर आती है। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले न जाने कितने युवा सिर्फ इसी वजह से असफल होते हैं कि वह हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा में पठन सामग्री की कमी है। स्थिति इससे अधिक बिगड़ने की ओर है, क्योंकि सितंबर के पंद्रह दिन ही तो हम हिंदी भाषा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। इस स्थिति के लिए संपूर्ण भारतीय समाज जिम्मेदार है जो एक ओर अपनी संस्कृति का ढिंढोरा पीट कर विश्वगुरु बनने की बात करता है तो दूसरी ओर अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने के माध्यम यानी हिंदी भाषा को हेय दृष्टि से देखता है। यानी 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और'। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदी जो हिंदुस्तान की पहचान है, उसे सहेजें, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं, लेकिन उन्हें हिंदी में जीने के लिए प्रेरित करें। विज्ञापनों, पुस्तकों, पत्रिकाओं का लेखन हिंदी भाषा में करें। अपने जीवन में हिंदी शामिल करें, क्योंकि इसी से तो हमारा और भारतीय समाज का वजूद है, हिंदुस्तान का वजूद है, अगर हिंदी है तो हिंदुस्तान है।

● *दीपक, आर्यभट्ट महाविद्यालय, नई दिल्ली*

तकनीक की भाषा बने

हमारा समाज प्रायः आम बोल-चाल में हिंदी का प्रयोग करता है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो हम इसे अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना पसंद करते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोगों के मन में हिंदी के लिए क्या सम्मान है? जहां एक तरफ आंकड़े बताते हैं कि विदेशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, वहीं भारत में सिविल सेवा में हिंदी माध्यम के छात्रों का सफलता ग्राफ गिरता जा रहा है। जानकार इसका मुख्य कारण पाठ्यसामग्री हिंदी में उपलब्ध न होना बताते हैं। हिंदी में जो पुस्तकें हैं भी, वे अनुवादित हैं। यदि वास्तव में हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको इसके प्रचार-प्रसार को रोक कर इसको विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाना होगा।

● *संदीप कुमार, ईसीसी, प्रयागराज*

आरक्षण की समीक्षा

हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी और एससी-एसटी की आरक्षण सीमा को अट्ठावन से बढ़ा कर बयासी फीसद कर दिया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को भी कुल बचे पद का दस फीसद आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है। विडंबना यह है कि आजादी के सात दशक बाद आरक्षण की व्यवस्था को जहां धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए था, वहां अब इसका इस्तेमाल सरकारें समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी वैमनस्यता पैदा करने में कर रही हैं। आरक्षण आज हर पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक बन चुका है। दशकों से चले आ रही आरक्षण व्यवस्था का लाभ कितने फीसद लोगों को मिला है, इसके लिए सरकार को स्पष्ट आंकड़े जुटाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य स्तर पर आंकड़े जुटा कर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वाकई अब तक आरक्षण का लाभ कितने फीसद लोगों को मिला है। आमतौर पर देखने को यही मिला है कि आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। जरूरतमंद एर हकदार लोग इससे वंचित रह जाते हैं। 1947 के भारत और अब के भारत में काफी बदलाव आ चुका है। आरक्षण से जहां एक वर्ग वर्षों से लाभान्वित हो ता आ रहा है, तो दूसरी तरफ सामान्य वर्ग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसमे कोई दो मत नही है कि इतने वर्षों में सामान्य वर्ग को आरक्षण की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आरक्षण बढ़ने से सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्गों के पदों में कमी आएगी। आरक्षण की व्यवस्था जहां एक वर्ग के लिए हितकर है, वहीं दूसरे वर्गों की यह उपेक्षा करती है। सरकार को चाहिए कि इसकी जमीनी स्तर पर जानकारी हासिल करके ही इसकी समीक्षा कर इसे बढ़ाने का निर्णय ले।

● *अमित पांडेय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)*

जवाबदेही जरूरी

नए मोटर वाहन कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर विवाद जारी है और लोगों में रोष भी है। कुछ राज्य सरकारें भी खुल कर इसके विरोध में आ गई हैं। यह तो सभी जानते हैं कि बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए, मोबाइल पर बात करते गाड़ी चलाना जैसी आदतें गंभीर मुसीबत का कारण बन सकती हैं। मगर लोगों में सतर्क न रहने की आदत बन गई है, तो इसकी कुछ वजह यातायात पुलिस की लापरवाही भी है। अक्सर वह कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी दबाव में आकर या कुछ रिश्वत लेकर छोड़ देती है। इस तरह लोगों में धारणा बन गई है कि अगर वे कोई गलती करेंगे तो आसानी से बच निकलेंगे। इसलिए केवल जुर्माने के भय से लोगों में कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को खत्म करने का दावा नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित महकमों को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है।

● *अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com